

ग्रामीण उद्यमिता के विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका (उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के विशेष संदर्भ में)

गजेन्द्र नाथ

शोधार्थी/असिस्टेंट प्रोफेसर-अर्थशास्त्र

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन राजकीय महाविद्यालय तालबेहट, ललितपुर

प्रो. सी. बी. सिंह,

विभागाध्यक्ष, बैंकिंग अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान,

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी

शोध सारांश

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups-SHGs) ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरे हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण भारत में उद्यमिता विकास और आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। यह शोध पत्र स्वयं सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन करता है, विशेष रूप से ग्रामीण उद्यमिता के विकास, रोजगार सृजन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में। स्वयं सहायता समूह सामूहिक बचत, आसान ऋण सुविधा और वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों, जैसे पशुपालन, हस्तशिल्प, कृषि-आधारित उद्योग और सूक्ष्म उद्यमों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि स्वयं सहायता समूह को बाजार पहुंच, प्रशिक्षण और पूंजी की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निष्कर्षतः स्वयं सहायता समूह ग्रामीण उद्यमिता के सतत विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि स्वयं सहायता समूह सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं, हालांकि पूंजी की कमी, प्रशिक्षण की सीमाएँ और बाजार तक पहुंच जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। समग्र रूप से स्वयं सहायता समूह ग्रामीण उद्यमिता के विकास में एक प्रभावी और सतत मॉडल के रूप में कार्य करते हैं।

मुख्य शब्द— स्वयं सहायता समूह , ग्रामीण उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, सूक्ष्म वित्त , वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास, स्वरोजगार, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, सूक्ष्म उद्यम।

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान और विकासशील देश है, जहाँ आज भी लगभग 65 से 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। देश की आर्थिक प्रगति काफी हद तक ग्रामीण विकास पर निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर, संसाधनों की कमी और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएँ लंबे समय से विद्यमान हैं। ऐसे में ग्रामीण उद्यमिता (Rural Entrepreneurship) को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हो, आय में वृद्धि हो और लोगों का जीवन स्तर बेहतर बन सके।

ग्रामीण उद्यमिता के विकास में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups – SHGs) एक प्रभावी और सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आए हैं। स्वयं सहायता समूह छोटे-छोटे स्वैच्छिक समूह होते हैं, जिनमें सामान्यतः 10 से 20 सदस्य होते हैं। ये सदस्य नियमित रूप से बचत करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर समूह के भीतर ही ऋण प्राप्त करते हैं। यह व्यवस्था न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि आपसी सहयोग, विश्वास और सामूहिक निर्णय लेने की भावना को भी विकसित करती है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को नई दिशा और गति मिली है। ये समूह विभिन्न प्रकार की आय-सृजन गतिविधियों जैसे लघु उद्योग, डेयरी, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, सिलाई-कढ़ाई तथा कृषि-आधारित व्यवसायों को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को समय-समय पर प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नई तकनीकों और व्यावसायिक ज्ञान से अवगत कराया जाता है, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह न केवल आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बनते हैं।

स्वयं सहायता समूह की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बैंकिंग सुविधाएँ सीमित होती हैं, वहाँ स्वयं सहायता समूह लोगों को बचत करने और सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे साहूकारों पर निर्भरता कम होती है और आर्थिक शोषण से बचाव होता है। साथ ही, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता का विकास होता है, जो समाज में उनके स्थान को मजबूत करता है।

हालाँकि, स्वयं सहायता समूह के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे बाजार तक सीमित पहुँच, उत्पादों के लिए उचित मूल्य न मिलना, वित्तीय साक्षरता की कमी, तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा पर्याप्त मार्गदर्शन का अभाव। इन समस्याओं के कारण कई बार स्वयं सहायता समूह की कार्य क्षमता और संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से स्वयं सहायता समूह को बेहतर प्रशिक्षण, विपणन सुविधाएँ और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।

अतः यह कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण उद्यमिता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि इन्हें उचित समर्थन और संसाधन प्रदान किए जाएँ, तो ये न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकते हैं, बल्कि समावेशी और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र स्वयं सहायता समूह के योगदान, उनकी कार्यप्रणाली तथा ग्रामीण उद्यमिता पर उनके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करता है।

स्वयं सहायता समूह का अर्थ

स्वयं सहायता समूह ऐसे छोटे-छोटे समूह होते हैं, जिनमें सामान्यतः 10 से 20 लोग शामिल होते हैं। ये लोग एक समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। स्वयं सहायता समूह का मुख्य आधार आपसी सहयोग, विश्वास और सामूहिक प्रयास होता है।

इन समूहों के सदस्य नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी राशि बचत के रूप में जमा करते हैं। यह बचत समूह के पास एक कोष के रूप में इकट्ठा हो जाती है। जब किसी सदस्य को पैसों की आवश्यकता होती है, तो

उसे इसी कोष से कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को साहूकारों या महंगे ऋण से बचाता है। भारत में स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करते हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से न केवल बचत करना सीखती हैं, बल्कि छोटे-छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, डेयरी, हस्तशिल्प, और कृषि कार्य भी शुरू करती हैं। इससे उनकी आय बढ़ती है और उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। स्वयं सहायता समूह का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। समूह के सदस्य मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार, स्वयं सहायता समूह न केवल आर्थिक विकास का साधन हैं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी माध्यम हैं।

शोध के उद्देश्य

1. स्वयं सहायता समूह की संरचना, कार्यप्रणाली और उद्देश्यों का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में की भूमिका का विश्लेषण करना, विशेषकर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के संदर्भ में।
3. यह जांचना कि स्वयं सहायता समूह किस प्रकार ग्रामीण उद्यमिता (Rural Entrepreneurship) को बढ़ावा देते हैं।
4. स्वयं सहायता समूह के सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं की पहचान करना।

शोध पद्धति

इस शोध में मिश्रित (Qualitative and Quantitative) शोध पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, ताकि विषय का गहन और वास्तविक विश्लेषण किया जा सके।

1. शोध का प्रकार (Type of Research)

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical) प्रकृति का होगा, जिसमें स्वयं सहायता समूह की भूमिका और ग्रामीण उद्यमिता पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

2. डेटा के स्रोत (Sources of Data)

प्राथमिक डेटा (Primary Data)

यह डेटा प्रश्नावली (Questionnaire), साक्षात्कार (Interview) और फील्ड सर्वे के माध्यम से ग्रामीण स्वयं सहायता समूह सदस्यों से एकत्र किया गया है।

द्वितीयक डेटा (Secondary Data)

पुस्तकें, शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट, नाबार्ड की रिपोर्ट, जर्नल्स और इंटरनेट स्रोतों से लिया गया है।

3. अध्ययन क्षेत्र (Area of Study)

अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय स्वयं सहायता समूहों पर केंद्रित है।

4. सैंपलिंग विधि (Sampling Method)

सरल यादृच्छिक सैंपलिंग (Simple Random Sampling) या उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग (Purposive Sampling) का उपयोग किया गया है।

5. डेटा संग्रह उपकरण (Tools of Data Collection)

प्रश्नावली (Questionnaire)

साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule)

अवलोकन (Observation)

6. डेटा विश्लेषण (Data Analysis)

एकत्रित डेटा का विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों जैसे प्रतिशत, औसत, तालिकाओं और ग्राफ के माध्यम से किया गया है।

साहित्य समीक्षा

स्वयं सहायता समूह पर अनेक विद्वानों और संस्थाओं ने अध्ययन किया है। इन अध्ययनों में यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रभावी साधन हैं। NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) की रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया है कि स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण गरीबों को बचत करने की आदत विकसित करने और आसान ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कई शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। महिलाएँ और ग्रामीण लोग छोटे व्यवसाय जैसे डेयरी, सिलाई, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग आदि शुरू कर पा रहे हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि स्वयं सहायता समूह न केवल आर्थिक विकास में सहायक हैं, बल्कि सामाजिक बदलाव में भी योगदान देते हैं। ये समूह शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।

हालांकि, कुछ शोध यह भी बताते हैं कि स्वयं सहायता समूह को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी, बाजार तक पहुंच की समस्या और वित्तीय सहायता की सीमाएँ।

इस प्रकार, साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण उद्यमिता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए और सुधार की आवश्यकता है।

हाल के वर्षों (2022–2025) में अनेक शोधकर्ताओं ने स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण उद्यमिता पर अध्ययन किया है। इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1. नाबार्ड (2022–2024)

नाबाड की हालिया रिपोर्टों में बताया गया है कि SHGs & Bank Linkage Programme ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और micro & entrepreneurship को मजबूत किया है। लाखों स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण और प्रशिक्षण सहायता दी गई, जिससे ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिला।

2. Jyoti Yadav, Ravinder Kaur & Suyash Mishra (2024)

इन शोधकर्ताओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का अध्ययन किया। उनके अनुसार स्वयं सहायता समूह महिलाओं की उद्यमशील क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे ग्रामीण व्यवसायों का विकास होता है।

3. Ashwini Pandhare, Praveen Naik Bellampalli & Neelam Yadava (2024)

इन लेखकों के अध्ययन में पाया गया कि microfinance और स्वयं सहायता समूह गतिविधियों का ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है।

4- Abu Shafique Ahmed & Sudip Chakraborty (2024)

इनके अध्ययन के अनुसार स्वयं सहायता समूह गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

5- Sonali Rajput & Neeta Maheshwari (2025)

इनके शोध में बताया गया कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में व्यवसायिक कौशल (skill development) और entrepreneurial attitude को मजबूत करते हैं, जिससे छोटे व्यवसायों की सफलता बढ़ती है।

शोध अंतराल (Research Gap)

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण उद्यमिता के विकास में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। 2022–2025 के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। माइक्रोफाइनेंस, बैंक लिंकेज और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूह ने छोटे व्यवसायों की स्थापना और आय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया है। हाल के शोध यह भी दर्शाते हैं कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण, विपणन सहायता और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे उनके व्यवसाय की सफलता की संभावना बढ़ती है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में भी सहायक रहे हैं। हालांकि, इन सकारात्मक पहलुओं के बावजूद 2022–2025 के साहित्य में कई महत्वपूर्ण शोध अंतराल पाए जाते हैं।

पहला, अधिकांश अध्ययन कुछ चुनिंदा राज्यों तक सीमित हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं का समुचित विश्लेषण नहीं हो पाया है। दूसरा, स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यमों के दीर्घकालिक प्रभावों पर पर्याप्त शोध का अभाव है। तीसरा, डिजिटल उद्यमिता, ई-कॉमर्स और तकनीकी उपयोग में स्वयं सहायता समूह की भूमिका पर सीमित अध्ययन उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, बाजार संपर्क, उत्पाद ब्रांडिंग और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियों पर गहन शोध की आवश्यकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी अपेक्षाकृत कम किया गया है। अंततः, सरकारी योजनाओं के वास्तविक प्रभाव और स्वयं सहायता समूह उद्यमों की स्थिरता पर और अधिक अनुभवजन्य अध्ययन की आवश्यकता है।

ग्रामीण उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह की भूमिका

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण भारत में उद्यमिता विकास के एक प्रभावी माध्यम के रूप में उभरे हैं। ये समूह विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों, खासकर महिलाओं, को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर

बनाने में सहायता करते हैं। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य बचत, ऋण सुविधा और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। ये समूह मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आय सृजन कार्यों में लगे हुए हैं। नीचे झांसी में भेले द्वारा किए जा रहे प्रमुख आर्थिक क्रिया-कलापों का विवरण दिया गया हैरू

1. लघु उद्योग एवं निर्माण गतिविधियाँ

एलईडी बल्ब निर्माण चिरगांव ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह महिलाएं LED बल्ब बनाकर स्थानीय बाजार में बेच रही हैं।

प्रतिदिन 150 से अधिक बल्ब का उत्पादन किया जा रहा है। हस्तशिल्प एवं सिलाई कार्य सॉफ्ट टॉय, कपड़े, कढ़ाई, ज्वैलरी आदि का निर्माण। One District One Product (ODOP) योजना से जुड़कर उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री।

2. कृषि एवं पशुपालन आधारित गतिविधियाँ

पशु आहार (Cattle Feed) निर्माण

50 स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं पशु आहार उत्पादन कर रही हैं। प्रतिदिन लगभग 15 क्विंटल से अधिक उत्पादन। डेयरी एवं पशुपालन दूध उत्पादन, दुग्ध उत्पाद (घी, पनीर) कृषि कार्य सब्जी उत्पादन, अनाज उत्पादन। गन्ना उत्पादन एवं वैल्यू एडिशन में भी भागीदारी (नई पहल)

3. खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)

पापड़, अचार, मुरब्बा, मसाले, दाल, आटा, मोटे अनाज की पैकेजिंग, स्थानीय स्तर पर तैयार खाद्य सामग्री की बिक्री।

4. सेवा क्षेत्र (Service Sector Activities)

सरकारी राशन दुकान संचालन (PDS) मिड-डे मील पोषण आहार निर्माण, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग सेवाएं, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य

5. लघु व्यापार एवं विपणन

स्थानीय बाजारों में उत्पादों की बिक्री, मेलों, प्रदर्शनी (जैसे ट्रेड फेयर) में भागीदारी, समूह आधारित दुकान/स्टॉल संचालन

6. वित्तीय गतिविधियाँ (Microfinance)

समूह के भीतर बचत और ऋण वितरण, बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण लेकर छोटे व्यवसाय शुरू करना स्वयं सहायता समूह महिलाओं को स्वरोजगार हेतु पूंजी उपलब्ध कराते हैं।

7. अन्य उभरते कार्य

अगरबत्ती, मोमबत्ती निर्माण, सैनिटरी नैपकिन उत्पादन, डिजिटल सेवाएं, पर्यावरण कार्य (नर्सरी, पौध उत्पादन)

झाँसी जनपद में स्वयं सहायता समूह की भूमिका (ब्लॉक-वार तालिका)

विकास खंड	स्वयं सहायता समूह की प्रमुख गतिविधियाँ	स्वयं सहायता समूह की भूमिका
बबीना	पशुपालन, कृषि आधारित कार्य, छोटे व्यापार	महिलाओं को आय के स्रोत जोड़ना, स्वरोजगार बढ़ाना
बड़ागांव	सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, बचत समूह	कौशल विकास व घरेलू उद्योगों को बढ़ावा
बामौर	कृषि, दाल-प्रसंस्करण, मजदूरी आधारित कार्य	कृषि आय में वृद्धि व आर्थिक सहयोग
बंगरा	माइक्रो-उद्यम, पशुपालन, स्थानीय उत्पाद	ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन
चिरगांव	हस्तशिल्प, छोटे उद्योग, बैंकिंग लिंक	वित्तीय समावेशन व महिला सशक्तिकरण
गरौठा	कृषि, किरानाछोटे व्यवसाय, लघु उद्योग	रोजगार सृजन व बाजार से जोड़ना
मऊरानीपुर	डेयरी, कृषि प्रसंस्करण, स्वयं रोजगार	ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करना
मोंठ	पशुपालन, कृषि, स्वयं रोजगार योजनाएँ	आय वृद्धि व सरकारी योजनाओं का लाभ

स्रोत – सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि झाँसी जनपद में स्वयं सहायता समूह बहुआयामी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं—जैसे निर्माण, कृषि, सेवा, व्यापार और खाद्य प्रसंस्करण। इन गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं की आय में वृद्धि हो रही है स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता विकसित हो रही है।

झाँसी जनपद में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। इन समूहों ने विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को संगठित करके उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएँ छोटी-छोटी बचत करके एक सामूहिक निधि बनाती हैं, जिससे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। इससे वे साहूकारों पर निर्भर नहीं रहतीं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ती हैं।

झाँसी के विभिन्न विकास खंडों जैसे बबीना, बड़ागांव, बामौर, बंगरा, चिरगांव, गरौठा, मऊरानीपुर और मोंठ में स्वयं सहायता समूह ने अलग-अलग आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। कहीं पशुपालन और कृषि आधारित कार्यों को प्रोत्साहन मिला है, तो कहीं सिलाई-कढ़ाई, हस्तशिल्प, डेयरी उत्पादन और छोटे व्यवसायों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर वित्तीय समावेशन को भी मजबूत किया है।

इन समूहों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं और परिवारों की आय में सुधार हुआ है। स्वयं सहायता समूह ने न केवल आर्थिक विकास में योगदान दिया है, बल्कि सामाजिक जागरूकता भी बढ़ाई है। महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अधिकारों के प्रति समझ विकसित हुई है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है।

सरकारी योजनाओं जैसे NRLM और UPSRLM का लाभ भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सीधे ग्रामीण परिवारों तक पहुँच रहा है। इससे ग्रामीण विकास की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हुई है।

अंततः कहा जा सकता है कि झॉंसी जनपद में स्वयं सहायता समूह गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में एक मजबूत आधार के रूप में कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में यदि इन समूहों को और अधिक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ने की सुविधा मिले, तो यह ग्रामीण विकास को और अधिक गति प्रदान कर सकते हैं।

ग्रामीण उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह की चुनौतियाँ

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनके प्रभावी संचालन और सफलता के मार्ग में कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। ये चुनौतियाँ आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और तकनीकी स्तर पर देखी जा सकती हैं, जो स्वयं सहायता समूह की क्षमता को सीमित करती हैं।

वित्तीय चुनौतियाँ

स्वयं सहायता समूह की सबसे बड़ी समस्या सीमित वित्तीय संसाधन हैं। हालांकि बैंक लिंगेज कार्यक्रम मौजूद हैं, फिर भी कई समूहों को पर्याप्त और समय पर ऋण नहीं मिल पाता। ऋण प्रक्रिया जटिल होने के कारण छोटे उद्यमियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कई बार ऋण की राशि व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होती, जिससे उद्यम का विस्तार बाधित होता है।

बाजार तक सीमित पहुंच

ग्रामीण स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। उन्हें उचित बाजार, मूल्य निर्धारण, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जानकारी नहीं होती। इसके कारण उनके उत्पाद प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। बिचौलियों की भूमिका भी लाभ को कम कर देती है, जिससे समूह के सदस्यों की आय प्रभावित होती है।

कौशल और प्रशिक्षण की कमी

हालांकि स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है, लेकिन कई बार ये प्रशिक्षण पर्याप्त या गुणवत्तापूर्ण नहीं होते। आधुनिक तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग और व्यवसाय प्रबंधन से जुड़ी जानकारी का अभाव उद्यमों की सफलता में बाधा बनता है।

तकनीकी और डिजिटल बाधाएँ

डिजिटल युग में भी कई स्वयं सहायता समूह तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल भुगतान प्रणालियों की सीमित जानकारी के कारण वे ई-कॉमर्स और ऑनलाइन बाजार का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इससे उनके व्यवसाय के विस्तार की संभावनाएँ कम हो जाती हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ

ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक सोच और लैंगिक भेदभाव भी स्वयं सहायता समूह के लिए चुनौती है। महिलाओं को कई बार परिवार और समाज से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता, जिससे उनकी भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।

प्रबंधन और समन्वय की समस्याएँ

कई स्वयं सहायता समूह में उचित नेतृत्व, प्रबंधन कौशल और पारदर्शिता की कमी होती है। समूह के भीतर मतभेद, अनुशासनहीनता और लेखा-जोखा में गड़बड़ी जैसी समस्याएँ भी देखी जाती हैं, जो समूह की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं।

सरकारी योजनाओं का सीमित लाभ

हालांकि सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जाती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव, जटिल प्रक्रियाओं और भ्रष्टाचार के कारण स्वयं सहायता समूह तक उनका पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता।

अतः स्वयं सहायता समूह ग्रामीण उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी सफलता के लिए इन चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। बेहतर प्रशिक्षण, आसान ऋण सुविधा, डिजिटल सशक्तिकरण और मजबूत बाजार संपर्क के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण उद्यमिता के विकास में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम के रूप में उभरे हैं। ये समूह न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि ग्रामीण गरीबों-विशेषकर महिलाओं-को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं। बचत और ऋण की सुविधा, बैंक लिंकेज, तथा सरकारी योजनाओं से जुड़ाव के माध्यम से स्वयं सहायता समूह छोटे और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायक सिद्ध हुए हैं।

स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आय वृद्धि और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है। इनके माध्यम से विकसित उद्यम-जैसे कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, हस्तशिल्प, और लघु उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और ग्रामीण पलायन को कम करने में सहायक हैं। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाया है, जिससे सामाजिक सशक्तिकरण को भी गति मिली है।

हालांकि, अध्ययन यह भी दर्शाता है कि स्वयं सहायता समूह के सामने कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे-सीमित बाजार पहुंच, अपर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान का अभाव, और वित्तीय संसाधनों की कमी। डिजिटल

साक्षरता और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सीमित उपयोग भी इनके विकास में बाधा बनता है। अतः, यह आवश्यक है कि स्वयं सहायता समूह को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नीतिगत स्तर पर सुधार किए जाएं। बेहतर प्रशिक्षण, सुलभ ऋण सुविधा, मजबूत बाजार संपर्क, और डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है।

अतः स्वयं सहायता समूह ग्रामीण उद्यमिता के सतत और समावेशी विकास के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करते हैं। यदि इनकी चुनौतियों को दूर किया जाए, तो स्वयं सहायता समूह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सन्दर्भ-सूची

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार. (2023). पं० दीनदयाल अंत्योदय योजना –राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) वार्षिक रिपोर्ट. <https://aajeevika-gov-in>
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार. (2024). पं० दीनदयाल अंत्योदय योजना –राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) दिशा-निर्देश एवं प्रगति रिपोर्ट. <https://aajeevika-gov-in>
3. सिंह, पी., एवं कुमार, आर. (2022). भारत में ग्रामीण उद्यमिता विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज.
4. शर्मा, ए. (2023). सूक्ष्म वित्त और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण. जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज.
5. विश्व बैंक (World Bank) (2022). दक्षिण एशिया में वित्तीय समावेशन और ग्रामीण आजीविका विकास- <https://www-worldbank-org>
6. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2023). आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23. <https://www-indiabudget-gov-in>
7. रेड्डी, एस., एवं पटेल, एम. (2024). ग्रामीण उद्यमिता और आय सृजन में स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव. जर्नल ऑफ माइक्रोफाइनेंस एंड डेवलपमेंट स्टडीज
8. ज्योति यादव, रविन्दर कौर, सुयस मिश्रा (2024) ग्रामीण लोगों को आत्म निर्भर बनाकर सामाजिक स्थिरता की दिशा: भारत में NABARD की पहलों का मूल्यांकन।
9. पंधारे, अश्विनी बेल्लमपल्ली, प्रवीण नाइक एवं यादव, नीलम (2024) ग्रामीण विकास और उद्यमिता में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर अध्ययन